

स्थिति में सुधार के लिए बुनियादी नगरीय मुख्य सुनिधाएं उपलब्ध कराई गईं, जबकि लक्ष्य 11.90 लाख स्लम निवासियों का था। ये आंकड़े पूरे देश से सम्बन्धित हैं।

(घ) मंत्रालय में शहर-वार सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि इस स्कीम को राज्य स्तर पर मानीटर किया जाता है। ई.आई.यू.एस. स्कीम के अन्तर्गत 1997-98 के दौरान लाभान्वित स्लम निवासियों के राज्यवार बेयौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

#### विवरण

यूनिट सं.

क्र. सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य 1997-98	उपलब्धि 1997-98	प्रतिशत उपलब्धि
1	आन्ध्र प्रदेश	142898	217697	1524
2	असम	7008	6549	94
3	बिहार	18000	2350	15
4	दिल्ली	50000	52025	104
5	गोवा	150	0	0
6	गुजरात	75000	117355	156
7	हरियाणा	99625	74589	75
8	हिमाचल प्रदेश	17500	23748	136
9	जम्मू और काश्मीर	70000	5213	7
10	कर्णाटक	70000	68087	97
11	केरल	15000	13078	87
12	मध्य प्रदेश	116232	199751	172
13	महाराष्ट्र	341230	292190	86
14	मणिपुर	6250	0	0
15	मेघालय	3750	3750	100
16	मिजोरम	1875	1000	53
17	उड़ीसा	10000	11500	115
18	पांडिचेरी	6500	6552	101
19	पंजाब	12500	569	5
20	राजस्थान	40000	54414	136
21	सिक्किम	1500	1500	100
22	तमिलनाडु	13500	17903	133
23	त्रिपुरा	15000	15000	100
24	उत्तर प्रदेश	156000	85270	55
25	प. बंगाल	30600	44969	147
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	400	400	100
	कुल जोड़	1189898	1315459	111

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न टाइप के फ्लैटों के लिए एकमुश्त भुगतान

3656. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) मध्यम आय वर्ग (एम.आई.जी.) और जनता फ्लैटों के लिए एकमुश्त भुगतान कुल लागत का पचास प्रतिशत और एस.एफ.एस. फ्लैटों के लिए कुल लागत का वब्बे प्रतिशत निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस निर्णय के बाद ये फ्लैट आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर शीघ्र विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):** (क) डी.डी.ए. ने सुचित किया है कि:

(I) किराया खरीद आधार पर मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणी के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन के मामलों में आबंटी को भूमि की लागत+निर्माण लागत का 30% आरंभिक जमा के रूप में देना होता है। फ्लैट की शेष लागत बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाती है।

(II) स्व. वित्त पोषित स्कीम (एस.एफ.एस.) फ्लैटों के मामले में आबंटियों को अनुमानित लागत का 90% चार छमाही किश्तों में निम्नलिखित लारणी के अनुसार देना होता है।

(1) 25% (प्रारंभिक जमा के रूप में दी गई राशि सहित) आबंटन के समय

(2) 20% अगले छः माह बाद

(3) 25% अगले छः माह बाद

(4) 20% अगले छः माह बाद

(5) शेष 10% वृद्धि सहित, यदि हो, कब्जा लेते समय।

तथापि, किसी पाकेट में निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार उस पाकेटों के सफल आवेदकों को निर्माण कार्य की स्थिति के आधार पर छमाही किश्तों की दो या तीन या चार किश्तें एक साथ जमा करने के लिए कहा जाता है।

(III) स्वक्तिपोषण स्कीम (एस.एफ.एस.) के तहत तैयार फ्लैटों को देते समय झा हो जाने के बाद पूरी निपटान कीमत मांगी जाती है।

(ख) जी, नहीं;

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### **Restructuring of CPWD**

3657. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether a working group of the Planning Commission, had recommended in 1990, the restructuring of the top setup of the Central Public Works Department, with a view to imparting greater autonomy of the Department;

(b) if so, the precise recommendations of the group and whether the same were accepted by Government; and

(c) what steps have since been taken for implementation thereof and the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The working Group had recommended the conversion of the top structure of CPWD into a Central Public Works Board. The reconstruction of the CPWD into a Board on the lines of Railway Board/Telecommunication Board has not been considered feasible due to following reasons:—

- (i) That CPWD is not a commercial organisation and it does not provide any service to the public. The CPWD is mainly a construction management agency which takes up the civil works of the Central Government except Finance, Railways, Atomic Energy etc. The works executed by the CPWD are broadly classified into three categories. The first category relates to the works which are financed from the plan provision of the Department of Urban Development and these comprises

construction of general pool office and residential accommodation. The second category comprises of works pertaining to other Ministries/Departments of the Government for which funds are also provided under the demands-for-grants for the CPWD but distinctly for each Ministry/Department. In the third category, the CPWD undertakes the deposit works from autonomous organisations, institutions, etc. In fact, the major part of the work load of CPWD comprises of the later two categories of works. The CPWD draws its budget from more than 30 Ministries/Departments for which administrative financial sanctions have to be accorded by the Ministries concerned. The CPWD even if converted into a Board would not be in a position to accord administrative and financial sanctions for works belonging to other Departments and the very rationale of converting CPWD into a Board would be lost. This would be evident from the fact that nearly 60% of the works executed by the CPWD pertain to other Ministries/Departments. During 1995-96, out of Rs. 1500 crores of works executed by the CPWD, works costing Rs. 940 crores pertained to other Ministries. The CPWD cannot even decide the *inter-se* priorities as these are to be decided by the respective Ministries/Departments.

- (ii) The DG(W), CPWD, has already been delegated full powers to award works. Even for administrative and financial sanctions, only those cases come to the Ministry where construction of general pool office/ residential accommodation is involved.

This matter was recently examined by the Fifth Pay Commission also which did not agree with the idea of converting CPWD into a Board.